भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 375

(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तेलंगाना के पेड्डापल्ली में पीएमजीएसवाई

375. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेलंगाना , विशेषकर पेड्डापल्ली में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है और तेलंगाना को कितना बजट आवंटित किया गया हैं;

(ख) तेलंगाना के पिछड़े जिलों में निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है , साथ ही लंबित परियोजनाओं की स्थिति और देरी के कारण क्या हैं; और

(ग) धनराशि के उपयोग में खामियों को दूर करने और ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न घटकों/कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत तेलंगाना में कुल 2,088.05 किलोमीटर और पेड्डापल्ली जिले में 41.38 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। कार्यक्षेत्रवार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > Progress Monitoring > State MPR Abstract Report पर देखा जा सकता है। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	निर्मित सड़क लंबाई (किमी में)	
	तेलंगाना	पेड्डापल्ली

2020-21	315.39	-
2021-22	630.83	18.13
2022-23	496.01	4.24
2023-24	492.93	13.33
2024-25	152.89	5.68
कुल:	**2088.05**	**41.38**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 837.34 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछले पाँच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**कुल आवंटित/जारी बजट (रुपये करोड़ में)**
2020-21	0
2021-22	86.38
2022-23	321.43
2023-24	296.96
2024-25	132.57
कुल:	**837.34**

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- । भारत सरकार का एक विशेष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क के अनुसार सभी पात्र संपर्कविहीन बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ना है। इसकी शुरुआत से ही , तेलंगाना के तीन चिन्हित पिछड़े जिलों आदिलाबाद, खम्मम और करीमनगर में पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 1,641 किलोमीटर लंबी कुल 446 सड़कों को मंजूरी दी गई है , जिनमें से 1,439 किलोमीटर लंबी कुल 403 सड़कों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। 144 किलोमीटर लंबी कुल 43 सड़कों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। कार्यक्रम/घटक-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > Progress Monitoring > State Abstract Report पर देखा जा सकता है।

योजना को कार्यान्वित करते समय भूमि उपलब्धता/अधिग्रहण , वन मंजूरी, राज्यों की कम संविदा क्षमता, निविदाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं की कमी , राज्यों की निधि जारी करने की

वित्तीय क्षमता, राज्यों/राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) की निष्पादन क्षमता जैसी चुनौतियाँ सामने आईं, जिससे योजना की समग्र प्रगति प्रभावित हुई।

(ग) 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। पीएमजीएसवाई कार्यों को समय पर पूरा करने में राज्यों को बजटीय सहायता की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

i. राज्यों से निष्पादन क्षमता और संविदा क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

ii. बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

iii. क्षमता निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

iv. उस जोन के राज्यों के समूह के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर वास्तविक और वित्तीय मापदंडों की नियमित और संरचित समीक्षा की जाती है।

***